

संक्षिप्त समाचार

बकरीद को लेकर नगर थाना में शांति समिति की हुई बैठक

कानून हाथ मे लिया तो नहीं मिलगा राहत- एसडापाआ



स्पाइ- आवगाश मडल

पाकुड़: बकराद पव का लकर पाकुड़ नगर थाना पारसर म राववार का
शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ
दयानंद आजाद ने की, वहाँ बीड़ीओ समीर अल्फेड मुर्मु समेत थाना क्षेत्र के
कई गणमान्य लोग, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि भी माजूद रहे एसडीपीओ
दयानंद आजाद ने कहा कि उपर्युक्त पाकुड़ के निर्देश पर यह बैठक बुलाई
गई है ताकि बकरीद के मौके पर किसी भी प्रकार की अफवाह या शांति भग्न
करने वाली घटनाओं पर धृति से ही कड़ी नजर रखी जा सके। उन्होंने स्पष्ट
शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या अफवाह फैलाने
वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सभी समदाय एकजट होकर मनाएं त्योहार- बीड़ीओ

तमा समुदाय इकजुट हाकर नमाए त्वाहार- बाडाज

बठक म बाड़ाआ समार अल्फ्रेड मुमू न कहा। कपाकुड़ का गणा-जमुना तहजीब हमेसा मिसाल रही है। बकरीद जैसे पर्व को आपसी भाईंचरों और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। उठनें लोगों से अपील की कि प्रशासन को सहयोग करें और किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत सूचना दें। प्रशासन ने दिए निर्देश, पर्व पर दिखेगा चौकसी का माहौल

बैठक में माजूद लोगों से सुझाव भी लिए गए। तय हुआ कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी और ड्रोन से भी निगरानी की जा सकती है। अफसरों ने साफ किया कि त्योहार के दौरान कानून हो कि कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय सेवकों के सम्मान में इस सभा का आयोजन किया जा रहा है,

वट सावित्री पूजा को ले खरीदारी को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़



देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

देवघर. शहर के बाजारों में वट सावित्री पूजा को लेकर रविवार को बाजारों में महिलाओं और पुरुषों की भीड़ उमड़ी। वट सावित्री पर्व सोमवार को का आयोजित होगा। इसे लेकर बाजारों में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। महिलाओं ने बास के पंखा, बांस के डाला और फल, फूल, श्रांगार की सामने की खबर खरीदारी की। विवाहिता के लिए वट सावित्री व्रत हाथ से बने बास के पंखे और बस की डाली का विशेष इस पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। विवाहित महिला इस दिन व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो स्त्री इस व्रत को सच्चे मन से रखती है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि पति पर आई सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है, साथ ही भविष्य भी बेहतर होता है।

समाजसेविका सावित्री देवी के निधन पर^१ शोक सभा का हुआ आयोजन

दिव्य दिनकर सवाददाता



रिपोर्ट - प्रमोद कुमार सिंह

औरंगाबाद :- बिहार सरकार दे
मंत्री मंगल पाण्डेय स्वास्थ्य एवं विधि
विभाग, बिहार सरकार द्वारा औरंगाबाद
जिला के कुटुंबा प्रखण्ड में 19.0
करोड़ रुपये को लागत से बनने वाला
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 31 प्री
फैब हेट्प एंड वेलनेस सेंटर व
शिलान्यास किया गया। बिहार सरकार
प्रदेशवासियों को बैठतर, सुल

एवं सशक्त स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सतत प्रयासरत है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। विहार सरकार द्वारा औरंगाबाद जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्व में मॉडल अस्पताल, औरंगाबाद जा रहाना प्राप्ति आवे

दैरान किया गया था। वर्तमान में 21 करोड़ रुपये की लागत से मात्र शिशु अस्पताल, औरंगाबाद का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। सदर अस्पताल परिसर में 2.5 करोड़ रुपये की लागत से प्री-फैब पीआईसीयू अस्पताल तथा 7.5 करोड़ रुपये की लागत से 100 बेड प्री-फैब फील्ड अस्पताल, जहांगौर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हाल ही में चिंचे में 24 अधिकारक पाठ्यक्रम

झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की बैठक संपन्न

देवघर से दिव्य दिनकर
संवाददाता प्रेम रंजन झा

आज दिनांक 25/05/2025
झारखण्ड राज्य आंगनबाड़ी सेविक
महायिका मंडल झारखण्ड जिला कमिटी

बकाया है यदि महिला सम्मान का पैमाना ढाई हजार ही है तो राज्य के इस नीति को बनाने वाले माननीय मंत्री विधायक और नौकर शाह अपनी लकंजरी बांगले गाड़ी ,वेतन भत्ता सुविधा को त्याग कर राज कोष में दान कर दे और हर महीने ढाई हजार रुशि वेतन के रूप में ले राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए घाटक मईया योजना को ऐसे प्रचार किया जा रहा है मानो यह भारत रत्न , पद्म श्री पद्म भूषण और सार्वप्रिय पुरस्कार है ।



अपनी राजनैतिक रोटी सरकार का खजाने को लुटाकर सेंकने के लिए मईया योजना लाया है। हम सबों का सरकार की इस दुष्ट नीति को समझना होगा और राज्य को बर्बाद करने पर तुली इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगा। शिक्षा जगत वे लिए अभिशप्य बनी झारखण्ड सरकार ने स्कूल पूर्व शिक्षा का केंद्र आंगनबाड़ी और स्कूली शिक्षा के केंद्र

सरकारी विद्यालयों को निजीकरण
करने और दालित, आदिवासी हरिजन
अल्प संख्यकों और कमजोर वर्ग वे
बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वे
लिए झारखंड सरकार ने शिक्षक क
प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक
आचार्य का नामकरण करण कर वण
से निर्धारित सम्मान जनक ग्रेड
4200, 4600, और 4800, क
विलोपित कर चाहिना कट ग्रेड

2400 और 2800 देकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिभा को अपमानित कर दिया है । शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में परीक्षा के चरण बढ़ाते गए और ग्रेड पे बढ़ती महंगाई में घटा कर अपनी नीच सोच का परिचय दिया है कि राज्य की सत्ता अयोग्य लोगों के हाथों में है । शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लोहे के गेट के समान बनाकर इसे अभेद्य किया गया है उसे नियुक्ति नहीं करनी है मामला कोर्ट में फंसा कर जनता में घड़ियाली आंसू बहाकर सहानुभति लेना है । दलित आदिवासी हरिजन और अल्पसंख्यक के प्रति झूठी प्रेम दिखा कर पूरी अर्थ व्यवस्था को बर्बाद करना इस सरकार की मंशा है । जिस सरकार के पास महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए एक स्वतंत्र मंत्री नहीं वह सरकार महिला सम्मान की बात पर बैनर पोस्टर में होडिंग लगा कर बड़ी बात करे तो यह भद्दा भजाक है । वर्तमान सरकार के शासन काल में चरम पर पहुंची भ्रष्टाचार के कारण आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तबाह है जिलों मानदेय रोके दे बर्खास्त कर दे, वार्किंग मानदेय वृद्धि नहीं दे, इसकी शिकायत और निवारण का रास्ता बताने वाले कोई भी है । आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों में नित दिन नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर प्रेशन करना आम बात हो गई है । आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के नाम बिना काम के स्मार्ट फोन दिया गया, इसके लियार्जी की व्यवस्था नहीं की गई दर्जनों काम सौंप कर महीने मानदेय बकाया रखना, ज्ञारखंड सरकार की महिला सम्मान की वही नीति है । मानदेय, पोषाहार, मकान किराया भुगतान में ही अव्यवस्था नहीं है बल्कि केंद्र के लिए मिलने वाले पोषाहार का बाजार दर से काफी अंत है ॥ सरकार अपनी नीति में बदलाव नहीं किया और झूठी महिला सम्मान के नाम पर राज्य में अपना प्रचार किया तो आंगनबाड़ी की महिलाएं सड़क पर उतर कर सरकार की फर्जी महिला सम्मान की नीति का पदार्पण करेंगी इसकी तैयारी राज्य कमिटी की बैठक में जल्द लिया जाएगा । आज कई बैठक में रुबी कुमारी, प्रमिला यादव, सुधा देवी, शनित कुमारी राखंडे देवी, विद्या देवी, सहित सैकड़ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने भाग लिया ।

सेना में दिखने लगा महिला शक्ति का दम

>> विचार

“ रक्षा बलों में लैगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की प्रगति धीमी रही है। लेकिन लोगों का मानना है कि इसमें लगातार प्रगति हुई है। अब एक साथ बहुत सारी महिलाएं प्रमुख भूमिकाओं में हैं। वे दूसरों के लिए रास्ता बना रही हैं। उनके प्रदर्शन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वे अच्छा काम कर रही हैं तो उन्हें स्वीकार करना आसान होगा और आने वाली महिलाओं के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिलाएं केवल 10 या 14 साल तक सेवा दे सकती हैं। इसके बाद वो सेवानिवृत हो जाती हैं। लेकिन अब उन्हें स्थायी कमीशन के लिए आवेदन करने का भी मौका मिलेगा। जिससे वो सेना में अपनी सेवाएं आगे भी जारी रख पाएंगी और ऐक के हिसाब से सेवानिवृत होंगी।

संपादकीय

गजा में भूख से मरते मासूम

हमास के हमले के बाद इंजराइल का प्रतिक्रिया ने अब बेहद त्रासद रुख अद्वितीय कर लिया है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब तमाम मानवीय तकाजों को ताक पर रख दिया गया है और प्रभावित इलाकों में लोग भूख से मरने को मजबूर हैं। इस बात की कोई फ़िक्रनहीं दिखती कि अब एकतरफा हो चुके युद्ध में मरने वाले निर्दीष और मासूम बच्चे हैं। गाजा में इंजराइल के हमलों में जो लोग मारे जा रहे हैं, वह एक पक्ष भर है। इसके समांतर त्रासद और भयावह यह है कि इंजराइल ने गाजा के प्रभावित इलाकों में मानवीय मदद पहुंचाने के भी सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। नतीजा यह है कि अब वहां लोगों और खासकर बच्चों के मारे जाने की बड़ी वजह भूखमरी बन गई है। गाजा के अस्पतालों में हजारों की तादाद में क्लोप्षण के शिकार ऐसे बच्चे जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, जिन्हें जान बचाने के लिए पेट भरने लायक खाना भी नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने यह घेतावनी जारी की थी कि अगर जल्दी मदद नहीं मिली, तो सिर्फ दो दिनों के भीतर चौदह हजार बच्चों की जान जा सकती है। दरअसल, करीब दो महीने से इंजराइल ने सभी खाद्य सहायता, दवा और अन्य सामान के गाजा के युद्ध प्रभावित इलाकों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जहां करीब बीस लाख फिलिस्तीनियों की आबादी रहती है। गाजा में रहने वाले ये लोग पूरी तरह बाहरी सहायता पर निर्भर हैं, क्योंकि इंजराइली हमले ने उस इलाके की सभी खाद्य उत्पादन क्षमताओं को तबाह कर दिया है। जाहिर है, अब गाजा में अकाल का खतरा भी सामने खड़ा है। मगर अफसोसनाक यह है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर तमाम अंतरराष्ट्रीय प्रयास इंजराइल को दोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। गाजा में इंजराइली हमले में अब तक साठ हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, जिनका हमास या आतंकवाद से कोई गास्ता नहीं था। सवाल है कि हमास के जिस हमले को मानवता के खिलाफ बता कर इंजराइल ने युद्ध छेड़ दिया, उसमें मासूमों को मार कर क्या हासिल हो रहा है।

आशीष जोशी
परीक्षाएं समाप्त होने के साथ ही प्रदेश के स्कूलों में ग्रीष्मावकाश भी शुरू हो गया है। जुलाई में सरकारी स्कूलों में नया शिक्षा सत्र भी शुरू हो जाएगा। लेकिन यक्ष प्रश्न यही बना हुआ है कि क्या इस बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हो पाएँगे। यह प्रश्न इसलिए भी कि पिछले सात साल से इस श्रेणी के शिक्षक अपने इच्छित स्थान पर पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में नवनियुक्त शिक्षक भी हैं, जिनका नियुक्ति के बाद एक बार भी तबादला नहीं हुआ। यों तो तबादल करना या न करना सरकार का विशेष अधिकार है लेकिन सिर्फ तृतीय श्रेणी शिक्षकों को ही तबादलों से वंचित करने पर खुद शिक्षक भी सवाल खड़े

स्वामित्वाधिकारी, गुद्रक और प्रकाशक व संपादक सरोज चाहरी द्वारा विजय प्रेस, नया टोला पटना से मुद्रित तथा 302, मा तारा कंपलेक्स, नारायण गूर्ति पथ, नागरथर कलाना, बाँटग रोड पटना से प्रकाशित! संपादक सरोज चाहरी, R.N.I. No:- BIHHIN/ 2016/72168

रमण सराफ धमारा
यी सेना में महिला शक्ति का दम दिखाई देने लगा है।
वाँ की तरह महिलाएं भी सेना में बढ़ चढ़कर अपनी योग्यता
दर्शन कर रही हैं। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में सेना

“ रक्षा बलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की प्रगति धीमी रही है। लेकिन लोगों का मानना है कि इसमें लगातार प्रगति हुई है। अब एक साथ बहुत सारी महिलाएं प्रमुख भूमिकाओं में हैं। वे दूसरों के लिए रास्ता बना रही हैं। उनके प्रदर्शन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वे अच्छा काम कर रही हैं तो उन्हें स्वीकार करना आसान होगा और आने वाली महिलाओं के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिलाएं केवल 10 या 14 साल तक सेवाएं दे सकती हैं। इसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाती है। लेकिन अब उन्हें स्थायी कमीशन के लिए आवेदन करने का भी मौका मिलेगा। जिससे वो सेना में अपनी सेवाएं आगे भी जारी रख पाएंगी और ऐक के हिसाब से सेवानिवृत्त होंगी।



जबकि 155 महिलाएं एयर मेन (अग्निवार) के रूप में सेवा दे रही है। भारतीय नौसेना में 580 महिलाएं अधिकारी के रूप में सेवारत हैं जबकि 727 महिलाएं सैलर्स (अग्निवार) के तौर पर तैनात हैं इसी तरह 1212 महिलाएं भारतीय थल सेना के आर्मी मेडिकल कॉर्पस में 168 महिलाएं आर्मी डेंटल कार्स में और 3841 महिलाएं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कार्यरत हैं। 1151 महिलाएं नौसेना के मेडिकल कॉर्पस में 10 महिलाएं डेंटल कार्य और 380 महिलाएं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सेवारत हैं। 274 महिलाएं भारतीय वायु सेवा के मेडिकल कॉर्पस में पांच महिलाएं डेंटल कॉर्पस में और 425 महिलाएं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सेवारत हैं पहले महिलाओं को स्टार्ट सर्विस कमीशन में ही लिया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को सेना में स्थाई कमीशन मिलने लगा है। अब एनडीए की कुल सीटों का 10 प्रतिशत सीटों पर लड़कियां सिलेक्ट होती हैं और वह भी ओपन कंपटीशन में मुकाबला करके। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मार्च 2025 में संसद में बताया था कि 2022 में महिला कैडेट्स के पहले बैच की एंट्री के बाद से अब तक एनडीए में 126 महिलाओं को

डिमेशन मिला है। आम्स्ट फोसर्ज में आने के बाद उनके तए भी अवसर समान होते हैं। उनका कारियर प्रोग्रेस वैसा होगा जैसा लड़कों का होगा। सर्विस रूट समान होते हैं। अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी सेना में पूरी तरह जेंडर न्यूट्रलाइजेशन हो गया है सेना में आज हमारी हिला कॉम्पैट पायलट भी है। जो मिसाइल चलती है मौर्चे र भी जाती है। वह इंजीनियरिंग का कार्य भी देखती है और टेलाइट को भी नियंत्रित करती है। अब महिलाएं डिफेंस में करती हैं। टेक्निकल इंटेलिजेंस भी एकत्रित करती है। अभी तक आपने -सामने की लड़ाई में महिलाओं को नहीं जा जाता है। राजस्थान में द्वांड्युन जिले की स्काइड्रन लीडर घान सिंह 2016 में भारतीय वायु सेवा की तेजस फाइटर पाइटर में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। इससे पहले ह मिग 21 बाइसन फाइटर प्लेन भी उड़ा चुकी है। गृष्म पट्टन सालिया धारी वायु सेवा की ऐसी पहली महिला अधिकारी बनी है जो फंटलाइन काम्पैट यूनिट की कमान भाल रही है। फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली वह पहली महिला अधिकारी है। भारत की सशस्त्र सेना विकित्सा सेवा और थलसेना एवं नौसेना की चिकित्सा

भारत में कृषि संकट और खेत मज़दूरों की बदलती प्रकृति खून पर भारी सिंदूर-व्यापार!

हमास के हमले के बाद इजराइल को प्रतिक्रिया ने अब बेहद त्रासद रुख अद्वितीय कर लिया है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब तमाम मानवीय तकाजों को ताक पर रख दिया गया है और प्रभावित इलाकों में लोग भूख से मरने को मजबूर हैं। इस बात की कोई फिक्रनहीं दिखती कि अब एकतरफा हो चुके युद्ध में मरने वाले निर्दीष और मासूम बच्चे हैं। गाजा में इजराइल के हमलों में जो लोग मारे जा रहे हैं, वह एक पक्ष भर है। इसके समांतर त्रासद और भयावह यह है कि इजराइल ने गाजा के प्रभावित इलाकों में मानवीय मदद पहुंचाने के भी सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। नतीजा यह है कि अब वहां लोगों और खासकर बच्चों के मारे जाने की बड़ी वजह भूखमरी बन गई है। गाजा के अस्पतालों में हजारों की तादाद में कुपोषण के शिकार ऐसे बच्चे जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, जिन्हें जान बचाने के लिए पेट भरने लायक खाना भी नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने यह घेतावनी जारी की थी कि अगर जल्दी मदद नहीं मिली, तो सिर्फ दो दिनों के भीतर चौदह हजार बच्चों की जान जा सकती है। दरअसल, कठीब दो महीने से इजराइल ने सभी खाद्य सहायता, दवा और अन्य सामान के गाजा के युद्ध प्रभावित इलाकों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जहां कठीब बीस लाख फिलिस्तीनियों की आबादी रहती है। गाजा में रहने वाले ये लोग पूरी तरह बाहरी सहायता पर निर्भार हैं, क्योंकि इजराइली हमले ने उस इलाके की सभी खाद्य उत्पादन क्षमताओं को तबाह कर दिया है। जाहिर है, अब गाजा में अकाल का खतरा भी सामने खड़ा है। मगर अफसोसनाक यह है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर तमाम अंतरराष्ट्रीय प्रयास इजराइल को दोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। गाजा में इजराइली हमले में अब तक साठ हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, जिनका हमास या आतंकवाद से कोई गारता नहीं था। संघर्ष है कि हमास के जिस हमले को मानवता के खिलाफ बता कर इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया, उसमें मासूमों को मार कर विद्युत विद्युत से जाता है। इसके लिए यह काम करते हैं, जैसे : सिर पर समान ढोने का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, निर्माण मजदूर का काम। मूलता वह हर काम करता है, जो उपलब्ध हो। खेती और कटाई के मौसम में भी वह गैर कृषि काम में दिहाड़ी करके अपनी अजीविका जुटाने का प्रयास करता है, जिससे कि परिवार का खर्च निकल सके। वह मनरेगा का भी नियमित मजदूर है, मगर वहां काम मिलना सरकार और पंचायत अधिकारियों की मरी पर निर्भर करता है। पशुपालन से भी परिवार को कुछ आय होती है। इसी गाँव के मरोती शिवराम मिश्किरे खेती के अलावा डाइवर का भी काम करते हैं। साथ ही, वे सुअर पालते हैं, जो उनके घर की आय का एक अतिरिक्त स्रोत है। इस गांव में किए गए सर्वेक्षण के दौरान मिले खेत मजदूरों के काम के विविध रूपों के ये दो उदाहरण ग्रामीण भारत में रोजगार और ग्रामीण मजदूरों की बदलती परिस्थितियों को दर्शाते हैं। इस बदलाव के कई कारण हैं, जिनमें मजदूरों का विस्थापन करने वाली मशीनों का अंधाधुंध उपयोग और खेतों पर निर्भर मजदूरों की बढ़ती संख्या शामिल है। हमारे सामने एक ऐसी स्थिति है, जहां मजदूरों की एक बड़ी संख्या है, जिन्हें ग्रामीण इलाकों में रोजगार नहीं मिलता और न ही पलायन करने के बाद शहरी केंद्रों में सुनिश्चित रोजगार मिलता है। भारत में बढ़ता कृषि संकट इस स्थिति का मूल कारण है। भारत में ग्रामीण आबादी को सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र से ही मिलता है। रोजगार में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है, जो 2017-18 में 44.1% से बढ़कर 2023-24 में 46.1% हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या 48.17 करोड़ थी। इसमें से 72 प्रतिशत कार्यबल ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और इसमें

स आध स आधक बाना ५-६.६ प्रांशत वा २६.३ करोड़ कृषि से जुड़े रेजगार में लगे हुए है। कृषि में काम करने वाले लोगों में मुख्य रूप से किसान और खेत मजदूर आते हैं। २०११ की जनगणना के अनुसार, इन दोनों समूहों के बीच में जमीन के मालिकाना हक्क की व्यवस्था एक मौलिक अंतर है, विशेष रूप से 'मालिकाना अधिकार', 'लीज का अधिकार' और 'भूमि अनुबंध' का होना या न होना। जहाँ एक तरफ एक किसान के पास ज़मीन होती है, नहीं तो लीज या फिर अनुबंध होता है, वहीं दूसरी तरफ खेत मजदूर भूमिहीन होते हैं और दूसरों की ज़मीन पर दिहाड़ी के लिए काम करते हैं। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसान भी मजबूरी में दूसरों के खेतों या अन्य कामों में मजदूरी करते हैं, जिससे किसान और मजदूर के बीच की रेखा धूंधली हो गई है। खेत मजदूर ग्रामीण सर्वठारा वर्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कृषि उत्पादन में लगे हुए है। वह ग्रामीण भारत में सबसे दबे-कुचले और हाशिए पर रहने वाला वर्ग है। खेत मजदूर सभी संसाधनों से चंचित हैं और उनमें से भी ज्यादातर भूमिहीन हैं, उनके पास उत्पादन के कोई साधन नहीं हैं और वे आजीविका के लिए अपने श्रम पर निर्भर हैं। अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के चलते वह शोषण का शिकार होते हैं और ज़मीदारों द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर काम करने को मजबूर हैं। ज्यादातर खेत मजदूरों के पास घर तक नहीं होते, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। वे न सिर्फ़ आर्थिक रूप से शोषित होते हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी उनका शोषण होता है और हाशिये पर धकेल दिए जाते हैं, जहाँ उन्हें भेदभाव और हिंसा का समान करना पड़ता है। महिला खेत मजदूरों को लैंगिक भेदभाव और सामाजिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है और पुरुषों के मुकाबले समान काम के लिए बहुत कम मजदूरी मिलती है। व्यवस्थित उत्पीड़न के कारण खेत मजदूर समग्र विकास की मुख्य धारा से बाहर हो जाते हैं, जिससे उनके जीवन में गरीबी और गैर-बराबरी का कुचक्कबना रहता है। ऐतिहासिक रूप से यह वर्ग शिक्षा से दूर रहा है और वर्तमान में भी इनके बच्चों को आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती है,

वाणिज विकास में बाधा और यूनियनों की कमी के ताकत, राजनीतिक चेतना मजदूर अपरिचित हजारों का सबसे नजदूरों का रहा है। बंधुआ न और अर्थिक शोषण का रूप है। यह गुलामी कर्ज से पैदा होती है और पीढ़ी-रहती है। देश के अलग-से अलग-अलग नामों से जैसे गुजरात में 'हाली', मध्य प्रदेश में 'हरवाहा', 'रोटी', कर्नाटक में 'जीथा' ति के बाद कई प्रवासी नी मजबूरियों के कारण नगाई गई तरह-तरह की नापड़ा, जिससे वे बंधुआ न न भरत में पहुँच गए। ग्रामीण अंतर्गत भूमिहीन परिवारों ने रोज़ी- रोटी के लिए मीर किसानों पर निर्भर हैं पर काम करने के लिए के कानूनी तौर पर बंधुआ नहीं है, पर बेरोजगारी के को कम मजदूरी वाले ड़ा जाता है। आजादी के तो तेज़ी से बढ़ने वाला वर्ग छठले तीन दशकों में अर्थक नीतियों के लागू होने तजदूरों की संख्या तेज़ी से 2001 तक के चार कृषि कार्यबल में खेत दा किसान थे। लेकिन, गणना में पहली बार यह नगण्यना से पता चला कि वर्षबल में किसानों की से कम (लगभग 45%) बकि खेत मजदूरों की 55% थी। असल संख्या की कुल संख्या 4 थी, जबकि खेतिहारा 14,43,29,833 थी। 100 किसानों पर 33 खेत न 2011 में यह संख्या किसानों पर 121 मजदूर तदूरों की संख्या बढ़ने के कई कारण ह, लाकन सबसे बड़ा कारण ह किसानों का गरीब होना, खासकर नवउदारवादी अर्थिक नीतियों के लागू होने के बाद। इन नीतियों के कारण कृषि को मिलने वाली सरकारी मदद कम हो गई, जिससे खेती की लागत बहुत बढ़ गई और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एपएसपी) या फसल की खरीद की कोई गारंटी नहीं रही। इस बजह से कृषि की पूरी प्रक्रिया ज्यादा अनिश्चित हो गई है। पहले किसानों के लिए सिर्फ मौसम की ही अनिश्चितता थी - वे सूखे और बारिश से डरते थे, लेकिन अब बाजार की अनिश्चितताएँ प्रकृति से भी ज्यादा कठिन और कठोर हैं। जब पूरी प्रक्रिया का एकमात्र लक्ष्य मुनाफा ही होता है, तो इसमें खेत मजदूरों की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं बचता। लगातार बने रहने वाला कृषि संकट छोटे और सीमांत किसानों को अपनी खेती से विस्थापित कर रहा है और वह किसानी छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि अब खेती उनके परिवार का पेट नहीं पाल पा रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के आँकड़ों पर आधारित अध्ययन बताते हैं कि लाखों छोटे किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है, खेती छोड़नी पड़ रही है और वह मजदूरों की कतारों में शामिल हो रहे हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि छोटे कारिगर भी अपना रोजगार खो रहे हैं और उन्हें खेत मजदूर के रूप में या अन्य छोटे-मोटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वर्तमान में खेत मजदूरों की संख्या किसानों से ज्यादा हो गई है, इसका मतलब है कि ज्यादा खेत मजदूरों की खेती पर निर्भरता बढ़ गई है। खेत मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। साथ ही, मरीनों और प्रौद्योगिकी के अंधाधुध इसेमाल ने कृषि में काम के दिन और कम कर दिए हैं। ग्रामीण भारत में बढ़ती बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में बढ़ते संकट और आमदनी की कमी के कारण युवाओं को अपनी जीविका के लिए पलायन करना पड़ रहा है। शहरों में अर्थिक संकट और बढ़ती बेरोजगारी एक जटिल स्थिति पैदा कर रही है। इन हालातों में, बड़ी संख्या में मजदूरों को गैर-कृषि क्षेत्रों में काम ढूँढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह स्थिति ग्रामीण भारत के मजदूरों को अपने पारवर के गुजार के लिए तरह-तरह के काम करने पर मजबूर कर रही है। ज्यादातर खेत मजदूर पूरे साल किसी एक काम तक सीमित नहीं रहते। लगभग सभी ग्रामीण मजदूर अलग-अलग अनुपात में खेती के काम में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा, वह सब समय-समय पर कई तरह के काम करते हैं - जैसे मनरेगा का काम, ईंट भट्टे पर मजदूरी, खेतों में मजदूरी या फिर आस-पास के छोटे शहरों में औद्योगिक काम। खेती में काम करने वाले खेत मजदूर और गैर-कृषि काम करने वाले मजदूरों के दो अलग-अलग समूह नहीं रह गए हैं। खेत मजदूर कृषि के साथ-साथ कई तरह के गैर-कृषि काम भी करते हैं, जिसमें शहरी इलाकों में पलायन करके काम करने वाले मजदूर भी शामिल हैं। फिर भी, ये मजदूर आंशिक रूप से गाँव और खेती से जुड़े रहते हैं और शहरी मजदूर वर्ग से कई मायनों में अलग हैं। इसका मतलब यह है कि गाँवों के बड़ी संख्या में मजदूर अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन वे खेती से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर खेत और ग्रामीण मजदूरों को सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी मिलती है। कम आमदनी और बढ़ती बेरोजगारी के बीच, खेत मजदूरों का जीवन कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक संस्थाओं पर निर्भर है। परंतु नवउदारवाद समर्थक पूँजीवादी ताकतें इन कल्याणकारी संस्थाओं के खिलाफ हैं। केरल की वाम मोर्चा सरकार को छोड़कर, पूरे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों का तेजी से निजीकरण हो रहा है। सभी तरह की पेंशन योजनाओं को सीमित करने की वजह से ग्रामीण भारत का एक बड़ा हिस्सा परेशान है। स्थिति इतनी खराब है कि मनरेगा के तहत रोजगार के अधिकार को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। संकट इतना गहरा हो चुका है कि खेत मजदूर आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो रहे हैं, जो उनकी भयावह स्थिति को दर्शाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, 2014 से अब तक कुल 40,685 खेत मजदूरों ने आत्महत्या की है। जिस समय खेत मजदूरों के रोजगार और रहन-सहन में बदलाव आ रहा है, तब गाँवों में एक नए अमीर वर्ग का भी उदय हुआ है।

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की स्थायी नीति बने



परित्यक्ता, दिव्यांगों के अलावा गंभीर रोग से ग्रसित आवेदकों को राहत मिली थी। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की। शिक्षकों के तबादले, नीति नहीं होने की आड़ में ही अटकाए जाते रहे हैं। कई कमेटियां व मन्त्रिमंडलीय उपसमिति के गठन के बाबजूद तबादलों को लेकर कोई कारणर नीति नहीं बन सकी है। वर्ष 1994 से लेकर वर्ष 2021 तक करीब आधा दर्जन कमेटियां तबादला नीति पर सुझाव देने को लेकर बनी लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। दरअसल तबादलों के लिए डिजायर संस्कृति ने ही कोई नीति नहीं बनने दी। प्रदेश में करीब साढ़े तीन लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं। इनमें से 72 हजार शिक्षक कई वर्षों से 'डार्क जोन' वाले जिलों में कार्यरत हैं। वे अपने गृह जिले के आसपास आना चाहते हैं। अब शिक्षक संगठनों ने तबादले नहीं खोलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश में अगले महीने तक तबादला प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो पाती तो फिर नया शिक्षा सत्र सुरु हो जाएगा। सरकार की शिक्षक संगठनों से भी विचार-विमर्श कर तबादलों की स्थायी नीति बनानी चाहिए ताकि असमंजस दूर हो सके।

मैं जमालपुर बोल रहा हूँ रेल मंत्री जी, मुझे आखिर कब मिलेगा रेल निर्माण कारखाना का दर्जा ?

‘रहनुमाओं की रहनुमाई’ देखिए कि देश को अब तक बिहार ने दिए सबसे अधिक ऐल मंत्री

रंजीत कुमार विद्यार्थी

मुंगेर : एशिया प्रसिद्ध एवं बिहार का पहला रेल कारखाना जमालपुर का तीन दिन पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव निरीक्षण करने आए और उन्होंने 350 करोड़ रुपए की लागत से जमालपुर रेल कारखाना के कार्यालय की सौंगत दी। लेकिन मुंगेर वासियों की ओर से पिछले 05 दशक से जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना की मांग को कोई तवज्ज्ञ नहीं दिए जाने से जिले वासी अपने आप का ठगा महसूस कर रहे हैं। बताते चले की 17 वर्षों के बाद किसी केंद्रीय रेल मंत्री ने एशिया प्रसिद्ध जमालपुर रेल कारखाना का निरीक्षण किया। जिले वासियों को आशा और उम्मीद थी कि 05 दशकों से उठ रहे निर्माण कारखाना की मांग को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रेल मंत्री ने जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना की दिशा में कोई चर्चा तक अपने संबोधन में नहीं किया। जिस कारण जिले के लोगों को निराशा हाथ लगी। जिले के लोग अब कहने लगे उम्माद या कि रेल नगा अखण्ड वैष्णव जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा प्रदान करेंगे, लेकिन उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। इधर, एनडीए के विपक्षी दल राजद, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बाम दल तथा जन सुराज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के इस कार्यक्रम को सिर्फ चुनावी कार्यक्रम करार दे रहे हैं। बताते चले की यहाँ के लोग जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना की मांग को लेकर पिछले 05 दशक से धरना प्रदर्शन सहित अन्य आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक लोगों का सपना साकार नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं प्रत्येक लोकसभा चुनाव में जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा दिलाना चुनावी मुझ भी बनता रहा है और हरक दल के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से वायदे भी करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद इसे निर्माण



कारखाना का दज दिलाएँगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 'रहनुमा' अपने वायदे को किसी सप्तमे की तरह विसार देते हैं। जिसको लेकर जिले वासियों में रहनुमाओं के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। वही, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगमन से पूर्व भाजपा - जदयु के नेता और कार्यकर्ता ढिंडोरा पीट रहे थे कि रेलमंत्री आएँगे और जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना का

र्दज्जा प्रदान करेंगे। जो कि ड्यूटा साबित हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो बार तथा रामविलास पारावान और लालू यादव एक-एक बार केंद्रीय रेल मंत्री रहे, लेकिन ऐश्विनी प्रसिद्ध एवं बिहार का पहला रेल कारखाना जमालपुर को निर्माण कारखाना का दज्जा नहीं दिला पाएँ। देश को अब तक सबसे अधिक रेल मंत्री बिहार ने दिए, फिर भी जमालपुर को

नहीं मिला निर्माण कारखाना का दर्जा बताते चले की देश को अब तक सबसे ज्यादा केंद्रीय रेल मंत्री बिहार ने दिए हैं। इसके बावजूद भी बिहार का सबसे पहला और एशिया प्रसिद्ध जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा नहीं मिल पाया है। जमालपुर रेल कारखाना की स्थापना ब्रिटिश शासन काल में 1862 ईस्वी में हुई थी। एक समय वहां 23, हजार से अधिक रेल कर्मी कार्यरत थे, लेकिन अभी वर्तमान में यहां मात्र 05 से 06 हजार ही रेल कर्मी ही कार्यरत हैं। दिन - प्रतिदिन रेल कर्मियों की छठनी और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस कारण जमालपुर रेल कारखाना के अस्तित्व पर संकट का बादल मंडरा रहा है।

बिहार से केंद्र सरकार में कौन-कौन रहे रेल मंत्री

केंद्र सरकार में बिहार

तक कुल नौ रेल मंत्री हर चुके हैं और देश का सबसे अधिक रेल मंत्री बिहार ने ही हीं दिए हैं। इसके बावजूद भी बिहार का सबसे पहला और एशिया प्रमुख जमालपुर रेल कारखाना की

की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया। जिसका परिणाम है कि आज जमालपुर रेल कारखाना के अस्तित्व पर संकट का बादल मंडरा रहा है।

सर्वदलीय संघर्ष समिति की बैठक में आंदोलन तेज करने का लिया गया निर्णय

मुगर विश्वावद्यालय मेवन निमाण के लिए सारा का आवटन मिलन के बाद मा काय नहा हो रहा शुरू

**जून माह में करा या मरा कर्त्तव्य पर किया जाएगा
आंदोलन**

A photograph showing a group of approximately 15-20 people, mostly men in traditional Indian attire like dhotis and kurta-pajamas, gathered outdoors. They are holding a large, colorful banner with text in Hindi. The banner reads "ਮੁਗੇਰ ਵਿਸ਼ਵਿਦਾਲਾਯ ਕਾ ਨਿਰਮਾਣ" (Opening of Moga Vishwavidyalay) and "ਨੌਵਾਗਢੀ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨਿ ਭੂਮੀ ਪਰ ਸ਼ੁਲੋਕ" (Shloka on the land of Nauvaghati). The background shows some trees and a clear sky.

अति शीर्ष कैसे हो इस पर ही आने वाले वक्ता अपना - अपना विचार व्यक्त करें। बैठक को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय विकास संघर्ष मोर्चा, मुगेर के संरक्षक नरेश सिंह यादव ने कहा कि मुगेर विश्वविद्यालय भवन उत्तम प्रशासन द्वारा नियन्त्रित जाना समझ से पेर है। अक्षय कुमार दास ने कहा कि नौवांगढ़ी का जनता यह कहती है की जब नौवांगढ़ी में विश्वविद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति मिल ही गई है तो संघर्ष करने से क्या लाभ भी। शक्तील अहमद ने विश्वविद्यालय का नाम कालाहाल कराया और तेज करना चाहिए, मुख्य अतिथि के तौर पर पर प्रसिद्ध प्रमंडलीय विकास संघर्ष मोर्चा मुगेर के संयोजक प्रो. विनय कुमार सुमन ने कहा कि मुगेर विश्वविद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के पारत नियम। बठक का गता साह, उपेंद्र मंडल, जयप्रकाश यादव अधिवक्ता, योगेंद्र यादव उर्फ योगी, विहार फूले अंबेडकर विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष मणि कुमार बौद्ध, पवन रंजन, पंकज कुमार दास, निरंजन यादव ने भी संबोधित किया।

या भूमि के पारजना का सात्वना दिन का निदेश पूर्व उपमुख्यमंत्री सह प्रातिष्ठ के नेता तेजस्वी यादव द्वारा मिलने पर मुगेर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहें अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव अपने समर्थकों के साथ मृतक के घर पहुंचे और मृतक के परिवार के लोगों से भेंट कर बीड़ियों कोंक्रीटिंग के द्वारा तेजस्वी यादव से बातचीत कराया। नेता प्रतिष्ठ के पीछे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दुख के इस घड़ी मैं एवं राजद परिवार आपके साथ खड़ा हूँ। पिछ्ले दिनों मैं जब मुगेर आया था तो रुट चार्ट में मय का नाम नहीं रहने के कारण मैं आप लोगों से मुलाकात

मुगेर में तूल पकड़ने लगा दबगो द्वारा स्कूल भवन तोड़कर रास्ता बनाने का मामला, आंक्रोश

बारयारपुर प्रथम क फुलाक्या मध्य विद्यालय के महान का ताङ्कर दबग बना एह सद्ग

सत्ता संरक्षित दबंगो के आगे
बेबस व लाजार दिख रही
जिला पशासन और पलिम

निरामिया ने चेतावनी दी है कि अगर अविलंब रास्ता निर्माण पर रोक नहीं लगाया गया तो चरणबद्ध आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशस्तान और पुलिस की होगी। स्कूल भवन ध्वस्त करने वाले दबंगों की मिरफतारी तथा शिक्षा विभाग के डीपीओ की खामोशी पर कार्रवाई की मांग करने वालों में बिहार फूले अंबेडकर विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष मणि कुमार अकेला, राजद के प्रदेश महासचिव प्रमोद यादव, पंकज कुमार यादव, मुगेर जिला राजद के महासचिव संतोष कुमार यादव, मीडिया सेल के मंटू शर्मा, संजय पास्तान, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य सह बेगूसराय जिला प्रभारी मो. डी.आर.पी.एस.पी.प्रियंका, नाम्रता भट्ट के जमालपुर नगर अध्यक्ष साई शकर, अरटीआई कार्यकर्ता सह अधिकर्ता ओमप्रकाश पोदार, नौवागढ़ी दक्षिणी पंचायत के पूर्व सरारंच सह राजद नेता सुनील भगत, नौवागढ़ी क्षेत्रीय विकास मंच के अध्यक्ष रंजीत कुमार, लोकमंच (सामाजिक - सांस्कृतिक संस्था) के महासचिव विनय कुमार सुमन सहित आदि सामाजिक एवं राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इसकी जांच कर विद्यालय तोड़ने वाले पर उचित करवाई करने की मांग किया है। वही, बरियापुर प्रखण्ड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजश सुबन्धु, प्रखण्ड बीस सूत्री के सदस्य चंद्र दिवाकर शर्मा, जदयू नेता शैलेंद्र कुमार सिंह, राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष देवकी नंदन सिंह, समाज सेवी शशि आनंद अलेबला, समाजसेवी विनय कुमार सिंह, आदि ने कड़ी करवाई करन की मांग शिक्षा विभाग के अगर सचिव तथा मुगेर के आयुक्त से कराने की मांग किया है।

A photograph capturing a scene of urban decay or demolition. In the foreground, a massive pile of rubble, consisting of broken bricks, concrete fragments, and twisted metal, dominates the left side. To the right, a two-story brick building stands partially collapsed, its upper structure leaning precariously. Further back, more brick buildings are visible, some with their roofs missing. The sky above is a uniform, pale blue, suggesting a clear day.

साहब मलिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता संजय केसरी, जन स्वराज विचार मंच के जिलाध्यक्ष संतोष सहाय, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पपू यादव, मीडिया सेल के अध्यक्ष मनोज क्रांति, कांग्रेस पार्टी के जमालपुर नगर अध्यक्ष साईं शंकर, आरटीआई कार्यकर्ता सह अधिवक्ता ओमप्रकाश पोद्दार, नौवांगढ़ी दक्षिणी पंचायत के पूर्व सरपंच सह राजद नेता सुनील भगत, नौवांगढ़ी क्षेत्रीय विकास मंच के अध्यक्ष रंजीत कुमार, लोकमंच(सामाजिक - सांस्कृतिक संस्था) के महासचिव विनय कुमार सुमन सहित आदि सामाजिक एवं राजनीति कार्यकर्ताओं ने बायान जारी कर दबंगों द्वारा फुलकिया मध्य विद्यालय के भवन को जेसीबी मशीन से तोड़कर काली मर्दिं के नाम पर रास्ता बनाए जाने की घटना की कड़ी निंदा की है। नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा है कि जब स्कूल की प्रधानाध्यापिका आरती विश्वकर्मा के द्वारा स्थानीय बरियारपुर थाना में विद्यालय भवन तोड़ने को लेकर 06 दिन पूर्व प्राथमिकी दर्ज कराई गई, फिर किस स्थिति में रास्ता का निर्माण दबंगों के द्वारा किया जा रहा है। जोड़ी पुलिस एवं शिक्षा विभाग सहित जिला प्रशासन के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाने के लिए काफी है। सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपने कहा कि मीडिया में डीएम एवं एसपी का बयान आया था कि किसी विद्यालय कीमत पर रास्ता का निर्माण नहीं हो सकता और दबंगों की जांचों उपरांत गिरफतार होगी। लेकिन बड़े दुर्भाय की बात कि डीएम और एसपी के संज्ञान स्कूल भवन दबंगों द्वारा ध्वस्त कर रास्ता निर्माण का मामला आने के बाद भी अब तक कर्तव्याइ नहीं हो पाई और ना ही रास्ता निर्माण पर कार्य पूर्ण रूप से रोका लगाया गया है। घटना 06 दिन बाद भी डीपीओ द्वारा घटनास्थल का मुयायाना नहीं किया जाना सवालों के घेरे में है। डीपीओ ने सिर्फ डीएम को अपनी रिपोर्ट भेजी है। किसी विद्यालय की बात कह अपना पल्ला झाड़ा

दिख रहे हैं। वहीं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मामले में खामोश है। शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन तथा

पुलिस विभाग की खामोशी और दबंग की दबंगई से अब यह सवाल उठने लगा है कि कहीं यह कार्य सत्ता संरक्षित दबंगों के द्वारा तो नहीं कराया जा रहा है। ऐसे बरियारपुर प्रखंड में सरेआम चर्चा है कि यह सब सारा खेल सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। जिस कारण से अधिकारी से लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण दबंगों के भय से मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लोकिन सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि भी दबंग के आगे लाचार और बेबस दिख रहे हैं। जिस कारण ग्रामीणों एवं शिक्षा प्रेमियों में क्षेत्रीय रहनुमाओं और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ डाईम और एसपी सहित स्थानीय थाना पुलिस के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है, जो किसी भी वक्त आदोलन का रूप अखतर कर सकता है। बरियारपुर प्रखंड के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इसकी जांच कर विद्यालय तोड़ने वाले पर उचित करवाई करने की मांग किया है। वही, बरियारपुर प्रखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजश सुबन्धु, प्रखंड बीस सूती के सदस्य चंद्र दिवाकर शर्मा, जदयू नेता शैलेंद्र कुमार सिंह, राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष देवकी नन्दन सिंह, समाज सेवी शशि आनंद अलेक्ट्रा, समाजसेवी विनय कुमार सिंह, आदि ने कड़ी करवाई करने की मांग शिक्षा विभाग के अपर सचिव तथा मुंगेर के आयुक्त से कराने की मांग किया है।

માન કર્મિયા વિલા કર રહા હતો

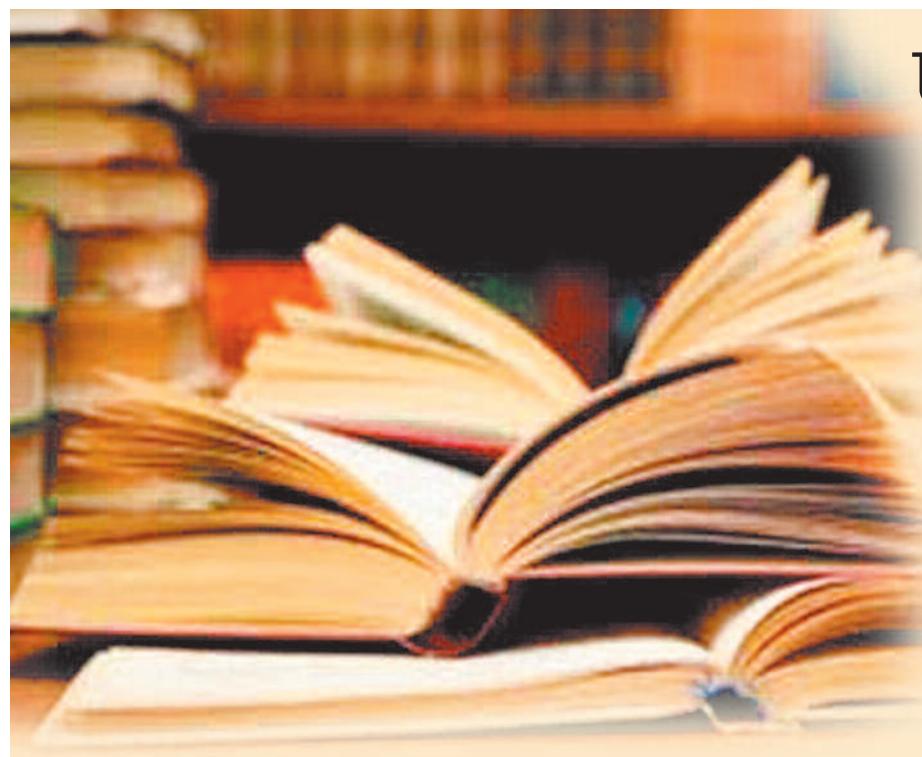
मार कासम किला का नाम क्या है?

जान का फ्लायट राजनीतिक साजिश : विनय कुमार सिंह

प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष सह ससद डा भाम सिह का बयान दुभावनापूर्ण प्रेतिवासिक धोगड़ें को मांपटायिक गंगा देने की हो रही कोशिश।

A portrait of a middle-aged man with dark hair and a prominent mustache. He is wearing a pair of round-framed glasses and a yellow long-sleeved kurta over a white collared shirt. He is also wearing light-colored pajama trousers. He is standing with his hands at his sides, looking directly at the camera. The background is a plain, light-colored wall.

लिए प्लासी की लड्डाई जीतने में मीर जाफर की भूमिका के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहले समर्थन दिया था मीर कासिम को 1760में बंगल का नवाब बनाया गया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को पद से हटा दिया। मीर कासिम ने 1762में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मगर स्थानांतरित कर दी ऐसा उन्हें राज्य के मामलों को बेहतर बनाने और अपनी व्यतिरिताको बनाए रखने के लिए किया था डॉ भीम सिंह इस ऐतिहासिक किला का नाम बदलकर सम्राट जरासंध करने की मांग राज्य तथा केंद्र सरकार से की है जो कहीं से भी उचित नहीं है। भाजपा पूर्व से ही ऐतिहासिक महत्व के उन स्थानों के नामों को बदलने का प्रयास करते रही है जो किसी मुस्लिम के नाम पर है ऐसा करना इतिहास के साथ क्रूर मजाक है इससे सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा होगा, जो कहीं से भी सर्विधान सम्पत नहीं है।



परीक्षा में सफलता पाने का नूल मंत्र

यदि तुम इस बार क्लास में फर्स्ट रैंक पर नहीं आई, तो यदि रखना कि तुम्हारे सारे गिप्टस कैंसल..., गोवा का ट्रिप तो कैंसल ही समझना यदि तुमने टॉप नहीं किया..., देखो बेटा कम नंबर लाकर हमारी नाक मत कटवा देना, यदि 90 प्रतिशत नहीं आए तो मनपसंद कालेज में एडमिशन नहीं मिलेगा..., ये सब एजाम से पहले हर पेरेंट्स को कहते हुए सुना जा सकता है, जो बच्चों में एजाम की टैशन दोगुना कर देते हैं।

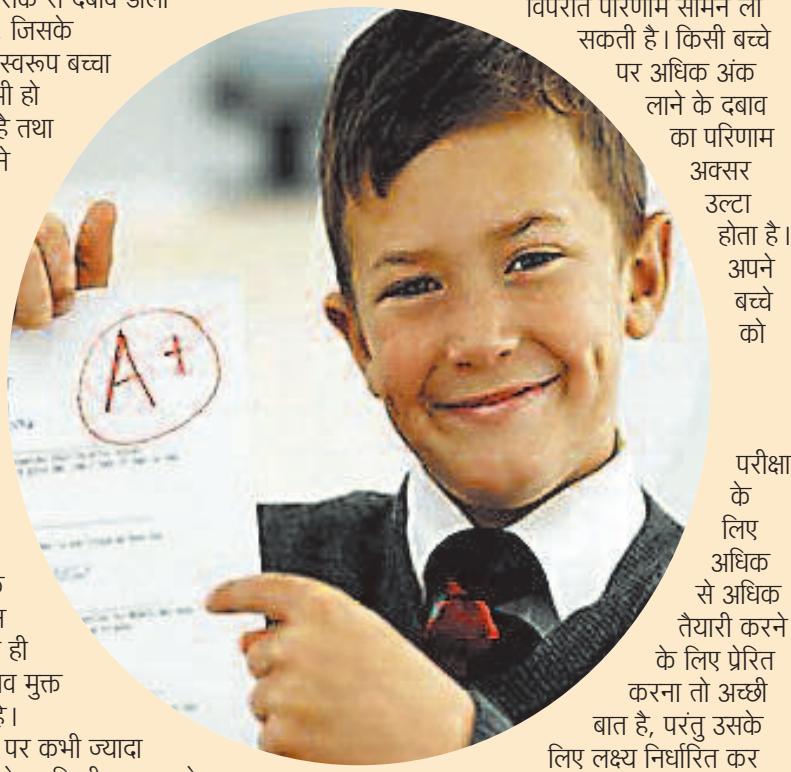
और उसके बाद ही उसे हल करें। हड्डवड़ी में प्रश्नपत्र हल करने की भूल न करें।
12 जिस प्रश्न को हल कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखें। इस दौरान अन्य प्रश्नों के बारे में विचार न करें, परंतु समय का ध्यान जरूर रखें।

न बनाएं दबाव

अपने बच्चे की क्षमता, रुचियाँ, इच्छा और क्लास में उसकी पोजीशन जानने की पेरेंट्स की कोई इच्छा नहीं रहती तथा बच्चे पर हर संभव तरीके से दबाव डाला जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बच्चा बीमार भी हो सकता है तथा फेल होने पर घातक कदम तक उठा लेता है।

अन्त बच्चे को बिना दबाव के इमिहान देने देना ही उसे तनाव मुक्त होता है।

उस पर कभी ज्यादा अंक लाने या किसी अन्य बच्चे जैसा बनने का दबाव न डालें। हर बच्चा अपने आप में विलक्षण होता है, बस उसे पहचानने की कोशिश करें। उसे आपके विवेकपूर्ण मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इसलिए उसकी असफलताओं पर उसे धिक्कारें नहीं, बल्कि विषम परिस्थितियों में उसे संभले रहने की



शिक्षा दें।

प्रेरित करें

हर बच्चा की बुद्धि, योग्यता और दक्षता भिन्न-भिन्न होती है, इसलिए तुलना विपरीत परिणाम सामने लाई जाती है। किसी बच्चे पर अधिक अंक लाने के दबाव का परिणाम अक्सर उल्टा होता है। अपने बच्चे को

परिक्षा के लिए अधिक से अधिक तैयारी करने के लिए प्रेरित करना तो अच्छी बात है, परंतु उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना तो दबाव बनाना गलत है।

इससे वह प्रेरित होने की अपेक्षा कुठित ज्यादा होता है। यदि बच्चा पेरेंट्स की इच्छानुसार परिणाम नहीं लाता तो उसे प्रताड़ित न करें। इस बात का विश्वास रखें कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स की अपेक्षाओं पर हमेशा

खरा उत्तरने का प्रयास करता है।

बच्चे का संबल बनें

जब वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह खुद ही बहुत निराशा, हताशा और आत्मतानि महसूस करता है। इस नाजुक समय में बच्चे को पेरेंट्स से संबल की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में बच्चे को अपमानित करने से बचें, क्योंकि यह वह संवेदनशील स्थिति होती है कि बच्चा आत्महत्या जैसे घातक कदम तक उठा सकता है।

बदलें दृष्टिकोण

यदि आशानुरूप परिणाम नहीं आए, तो उसे धीरज बधाएं और समझाएं कि कोई एक परीक्षा उनके लिए उससे महत्वपूर्ण नहीं है। अभी जीवन बहुत बड़ा है और उसे खुद को सिद्ध करने के अनेक मौके मिलेंगे। अभिभावकों का यह दृष्टिकोण बच्चे को अच्छा प्रदर्शन करने को प्रेरित करेगा।

रखें ध्यान

- 1 हर बच्चा किसी विशेष प्रतिभा के साथ पैदा होता है। इस बात को समझें व बच्चे को भी समझाएं।
- 2 आपने बच्चे को कामयाब नहीं, काबिल बनने के लिए पढ़ने को कहें।
- 3 उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का साधन मत समझें।
- 4 उसकी रुचियाँ और आदर्शों को समझाते हुए उसे समझने का प्रयास करें तथा उसी के अनुरूप करियर चयन में उसका साथ।
- 5 किसी बात को उस पर थोंपे नहीं, बल्कि उसे सिर्फ सुझाव दें।



स्वयं को तरक्की की राह पर परखें

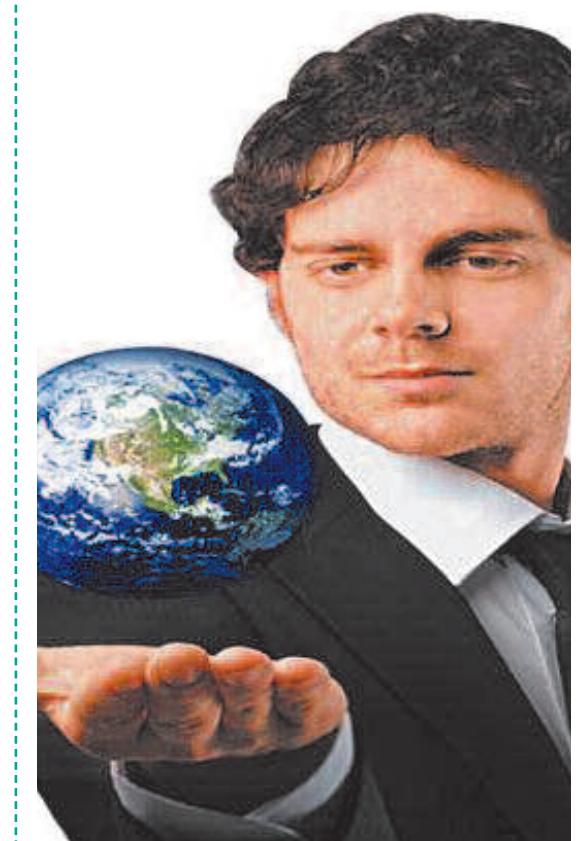
महाभारत का युद्ध कहीं बाहर नहीं, हमारे मन में ही चलता है। मन में अच्छे और बुरे विचारों की लड़ाई ही महाभारत है। यहां हमारा मन अर्जुन है और विवेक रूपी बैठना कृष्ण।

युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने सभी संगे-संबद्धियों, गुरुओं आदि को सामने देखते हैं तो उनके मन में मोह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये सब तो मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं युद्ध ही न करूँ। ऐसी बातें सोच कर दुखी अर्जुन भगवन कृष्ण की शरण में बैठ गए।

तब भगवन कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कहा, 'हे अर्जुन, जड़ मत बनो। यह तुम्हारे चरित्र के अनुरूप नहीं है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यागकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।'

कई बार व्यक्ति को किसी काम को करने से उसका दुर्बल मन डराता है। इस वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाता मगर याद रखना चाहिए कि जीवन में तरक्की दुर्बलता से नहीं बिल्कुल जटिल इरादों से मिलती है। दिनरात्या के हर काम को युद्ध की तरह समझना चाहिए और उसको उत्साह के साथ पूरा करना चाहिए। मन को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहिए। मन डराएगा लेकिन हमें डरना नहीं है। जीवन आगे बढ़ने के लिए है, डर कर या निराश होकर बैठ जाने के लिए नहीं।

कैसे प्रेरित करें व्यक्ति को उत्तरि व प्रगति की तरफ



असफलता के बीच से निकलती है सफलता



है। अगर हमारे अंदर इस तरह की सोच होती है कि आप आज और अगले दिन यात्रा कर रहे हैं तो हमें वर्तमान में जी कर यानी पूरी तरह से अटेंटिव होकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। इस दौरान उसे न तो नोकरी के बारे में सोचना चाहिए और न ही उसे परीक्षा के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। अगर वह स्टूडेंट, विभिन्न तरह के परिणामों यानी सवालों के धेर में पड़ जाएगा तो वह वर्तमान दौर की जरूरत पढ़ाई नहीं कर पाएगा। फिर न तो परीक्षा का रिजल्ट आगा और नहीं अच्छी नोकरी की उम्मीद की जा सकती है। हमें कभी भी शॉट कट कार्पूला नहीं अपनाना चाहिए। गौर करने की बात तो यह है कि शॉटकट हमेशा छोटा होता है और वह असफलता को आमंत्रित करता है। अगर गलती से रसफलता मिल भी जाती है तो वह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। हमें योंकि वह भी शॉट कट से निकलती है तो वह भी शॉट होती है। हमें जिदी में फूल-फूल पलान बनाना चाहिए ताकि सफलता में कोई भी संदेह न रह। सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि हर किसी को अपने अंदर आत्मविश्वास और भरोसा जरूर रखना चाहिए। व्यक्तिकि आत्मविश्वास होने पर बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ बढ़े ही आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। सफलता का एक अच्छा जरूरी सूत्र है कि हम अपने आपको आत्मसंतुलित रखें यानी कि अपने को नियमों के अनुसार होता रहा होगा।

सफलता का अनुपात कुछ समय ज्यादा तो कुछ समय कम होता है। कुछ लोगों का सफलता ज्यादा होता है और उसके लिए व्यक्ति को अपनी अपेक्षा करते हैं। जिसके लिए हम अपनी लाइफ का अच्छा खासा समय उसे सोचना में लगा देते हैं। यह अलग बात है कि हमारी जीवन का अनुपात कुछ समय ज्यादा तो कुछ समय कम होता है।

जीवन का लक्ष्य होता है। सभी लोग सफल होना चाहते हैं और उसके लिए व्यक्ति को अपेक्षा करते हैं।

जीवन का लक्ष्य होता है। सभी लोग सफल होना चाहते हैं और उसके लिए व्यक्ति को अपेक्षा करते हैं।

जीवन का लक्ष्य होता है। सभी लोग सफल होना चाहते हैं और उसके लिए व्यक्ति को अपेक्षा करते हैं।

जीवन का लक्ष्य होता है। सभी लोग सफल होना चाहते हैं और उसके लिए व्यक्ति को अपेक्षा करते हैं।

जीवन का लक्ष्य होता है। सभी लोग सफल होना चाहते हैं और उसके लिए व्यक्ति को अपेक्षा करते हैं।

जीवन का लक्ष्य होता है। सभी लोग सफल होना चाहते हैं और उसके लिए व्यक्ति को अपेक्षा करते हैं।

जीवन का लक्ष्य होता है। सभी लोग सफल होना चाहते हैं और उसके लिए व्यक्ति को अपेक्षा करते हैं।

जीवन का लक्ष्य होता है। सभी लोग सफल होना चाहते हैं और उसके लिए व्यक्ति को अपेक्षा करते हैं।

जीवन का लक्ष्य होता है। सभी लोग सफल होना चाहते हैं और उसके लिए व्यक्ति को अपेक्षा करते हैं।

जीवन का लक्ष्य होता है। सभी लोग सफल होना चाहते हैं और उसके लिए व्यक्ति को अपेक्षा करते हैं।

जीवन का लक्ष्य होता है। सभी लोग सफल होना चाहते हैं और उसके लिए व्यक्ति को अपेक्षा करते हैं।

जीवन का लक्ष्य होता है। सभी लोग सफल होना चाहते हैं और उसके लिए व्यक्ति को अपेक्षा करते हैं।

प्रभास को छोड़ अल्लू अर्जुन की फिल्म में सेट हो गई

दीपिका पादुकोण

इतने करोड़ में डील हुई फाइनल!



साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म काफी चर्चा बटोर रहा है. एटली के साथ एक्टर बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और जाह्नवी कपूर के शामिल होने की खबर है. प्रेमेंसी के बाद से एक्ट्रेस फिल्मी दुनिया में दोबारा कदम रखने के लिए तैयार हो चुकी हैं. हाल ही में आ रही खबर में ये सामने आ रहा है कि दीपिका ने इस फिल्म को ऑफिशियल साइन कर दिया है. दीपिका पादुकोण की जब से फिल्मों में वापसी की खबर सामने आई है, तभी से उनका नाम कई सारे प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है. फिल्मात एक्ट्रेस का नाम अल्लू अर्जुन की फिल्म के साथ जोड़ा जा रहा है, फेमस फिल्ममेकर एटली की डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म का टेटेटिव टाइटल AA22&A6 रखा गया है.

बताया जा रहा है कि फिल्म में 3 एक्ट्रेस शामिल होंगी. खबरों में बताया जा रहा है कि कई महीनों से दीपिका और एटली की इस फिल्म को लेकर बातचीत हो रही थी.

कितनी ले रही हैं फीस ?

700 करोड़ के बजट में बन रही इस फिल्म में दीपिका की फीस को लेकर भी

चर्चा बढ़ गई है. मिड-डे में छोपी रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस इस फिल्म के लिए

40 करोड़ रुपए फीस के तौर पर ले रही हैं. अब लोग जल्द ही इस फिल्म का

फैल्ड पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, पहले वो शाहरुख खान की फिल्म

'किंग' की शृंखला पूरी करेगी. किंग साल 2026 में रिलीज हो सकती है. इस फिल्म से

शाहरुख की बेटी सुहाना खान बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू करने जा रही है.

स्प्रिटर में भी आया था नाम

हालांकि, शाहरुख और अल्लू अर्जुन की फिल्मों के साथ ही साथ एक्ट्रेस का नाम प्रभास की

फिल्म 'स्प्रिटर' में भी जोड़ा जा रहा था. लेकिन, बाद में खबर आई कि संदीप रेड्डी वांगा की

डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म से दीपिका बाहर आ चुकी हैं. एटली के साथ दीपिका की ये

दूसरी फिल्म होगी. इससे पहले दोनों ने 'जवान' में साथ काम किया था. हालांकि, फिल्मों में

दीपिका की वापसी के लिए उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. एक्ट्रेस ने अपनी बेटी के

लिए कुछ बक्तव्य के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी.

पिता हीरा व्यापारी, भाई US में डॉक्टर...मैसूर सैंडल सोप की ब्रांड एंबेसडर बनीं

तमन्ना भाटिया को कितना जानते हैं आप?

कर्नाटक सरकार ने साउथ और बॉलीवुड फिल्मों की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को

मैसूर सैंडल सोप का ब्रांड एंबेसडर बनाया है. तमन्ना 2 साल के लिए 6.2

करोड़ रुपये चार्ज कर रही हैं. हालांकि, उन्हें ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने पर

बवाल भी मचा हुआ है. चलिए इस मामले के बीच आपको तमन्ना के बारे में

कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जो शायद ही आप जानते हों. तमन्ना का जन्म 21

दिसंबर 1989 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता का नाम संतोष भाटिया है, जो

एक हीरा व्यापारी है. उनकी मां का नाम

रजनी भाटिया है. एक्ट्रेस ने अपनी पढ़ाई

लिखाई मुंबई से की है. उन्होंने मानेकजी

कूपर एजेंसी ट्रस्ट से अपनी स्कूलिंग की.

वहाँ उन्होंने मुंबई के नेशनल कॉलेजे से

डिस्टेंस में आर्ट्स में बैचलर डिप्ली ली है.

तमन्ना भाटिया की फिल्मी करियर

तमन्ना के एक बड़े भाई भी हैं, जिनका नाम

आनंद भाटिया है. वो पेशे से एक डॉक्टर हैं

और अमेरिका में रहे हैं. बहुत सारे लोगों

को लगता है कि तमन्ना ने फिल्मी करियर साउथ फिल्मों से शुरू किया

था, लेकिन ऐसा नहीं है. उन्होंने साल 2005 में बॉलीवुड से ही डेब्यू किया था.

उनकी पहली फिल्म 'चांद से रौशन चेहरा' थी. उसी साल उन्होंने 'श्री' नाम

की फिल्म से तेलुगु सिनेमा में केंद्र

नाम की फिल्म से उन्होंने तमिल सिनेमा में डेब्यू किया था.

डेब्यू के बाद तमन्ना ने दो फिल्मों में काम किया, लेकिन वो लोगों की नज़रों में

साल 2015 में रिलीज हुई प्रभास की फिल्म 'बाहुबली' से आई. तमन्ना आज

के समय में बॉलीवुड का एक बड़ा नाम बन चुकी हैं. साल 2024 में रिलीज हुई

राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' में उन्होंने आइन नंबर

किया था. 'आज को रात' गाने में लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया था. उसके

बाद से वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहने लगी.

तमन्ना को ही ब्यांबो बनाया ब्रांड एंबेसडर ?

बहरहाल, चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर

तमन्ना को ही ब्यांबो एंबेसडर बनाया गया.

रशिमका मंदाना, कियारा आडवाणी, दीपिका

पादुकोण, पूजा हेंगड़े के हाते हुए तमन्ना को ही ब्यांबो

एंबेसडर के तौर पर ब्यांबो लिया गया. इस सवाल के

जवाब में कर्नाटक सरकार में मंत्री एम्बो पाटिल ने

कहा कि रशिमका ने कोई दूसरा प्रोजेक्ट साइन

किया था. पूजा और कियारा को लेना भी पॉसिबल

नहीं हुआ और दीपिका बजट में नहीं थी.

इन सबके नामों पर विचार हुआ था, लेकिन जब मुमाकिन नहीं हुआ तो तमन्ना को

लिया गया. उन्होंने ये भी कहा कि तमन्ना के इंस्टाग्राम पर 2.8 करोड़

फॉलोअर्स हैं और वो इसके लिए सही हैं.

15 साल की उम्र में खरीदा घर, अब
ये है मोहब्बतें की इस एक्ट्रेस ने बोर्ड
एक्जाम में कमाल कर दिया



फिल्म और टीवी की दुनिया में कई सारे ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी एक्टिंग की हार तरफ प्रशंसा भी देखने को मिल रही है. ऐसा ही किया है एक्ट्रेस रुहनिका धनवत ने. उन्होंने बलूले तो ये हैं ये भी मोहब्बतें ये यंग रूही भाज्ञा का रोल प्ले कर के सभी को खूब एंटरटेन किया. लेकिन इसी के साथ एक्ट्रेस ने पढ़ाई में भी मन लगाया. उनके 12th के बोर्ड एक्जाम में 91 पर्सेंट हासिल किए हैं. इस बात से वे कामी खुश भी हैं.

किसी भी चाइल्ड एक्टर के लिए अपने काम के साथ पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है.

एक्ट्रेस ने ये भी बताया है कि अपने बिजी शेइयूल के बीच कैसे उन्होंने वक्त निकालकर बोर्ड की तैयारी की और अच्छे नंबर लाने में भी सफल हुई. एक्ट्रेस ने इंटरव्यू के दौरान कहा— मैं बोर्ड में 91 पर्सेंट नंबर लाकर लेकिन काफी खुश महसूस कर रही हूं मैं बोर्ड में बहुत मेहनत की. मैंने 3 साल के लिए अपने एक्टिंग करियर तक पर रख दिया कि मैं पढ़ाई में बद्ध था और ध्यान लगा सकूं. अब मुझे लगता है कि मैं परेंट्स करना सफल हुआ. मेरे पैरेंट्स को भी मुश्किल पूरा भरोसा था कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगी और मैंने उन्हें सही साबित कर दिया. मेरी उम्र के दूसरे एक्टर्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं लेकिन मैंने पढ़ाई को छोड़ा.

आगे क्या करेगी रुहनिका ?

रुहनिका ने अपने आगे के प्लान्स के बारे में भी बताया है कि उन्होंने बताया कि— मैं अब महाराष्ट्र के कई अच्छे कॉलेज के इंटर्नेस एक्जाम की तैयारी कर रही हूं. अगर मेरे कॉलेज का शेइयूल फैलेक्सिसबल होगा तो मैं एक बार फिर से अपने एक्टिंग करियर की ओर आपना फोकस कर पाऊंगा'. मतलब सफल है कि एक्ट्रेस अपनी पढ़ाई को कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहती हैं लेकिन वे एक्टिंग से भी पूरी तरह से तौबा नहीं करना चाहती हैं. वे फिल्महाल 17 साल की ह